(c) whether the yardstick referred to in part (a) above was also applicable to the Northeast Frontier Railway which was a part of North Eastern Railway at that time and whether the same yardstick is still applicable or some changes have been made therein; and

(d) in either of the cases referred to in part (a) above the main reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

---

12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED BAN IMPOSED BY NEPAL GOVERNMENT ON IMPORT-EXPORT TRANSACTIONS BEING CARRIED ON IN NEPAL BY FOREIGN COMPANIES

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वाणिज्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

नेपाल सरकार द्वारा सभी विदेशी कम्पनियों पर, जिन में से अधिकांश में भारतीय हित अन्तर्निहित हैं, नेपाल में आयात-निर्यात सम्बन्धी व्यापार करने पर, प्रतिबन्ध लगाये जाने का समाचार ।

THE MINISTER OF COMMERCE (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA): Mr. Speaker, Sir, the Government of India had seen press reports of a Communique stated to have been issued by the Ministry of Commerce and Industry of Nepal according to which

"Exporters of finished jute products to countries other than the ones already importing the same from Nepal will henceforth be allowed an additional five per cent bonus in the form of incentives. But the firms run by the foreigners or in collaboration with them will not be permitted to export and import goods to and from Nepal.

The new steps are intended for making the trade diversification policy still more effective as well as to encourage the foreign investors to go into industrial ventures. The underlying purpose for not permitting foreign firms based in Nepal to export jute is to make use of their technical expertise and investment for the country's industrialisation. The principle purpose of the new arrangement is to render the policies and practice of trade diversification, import of development materials and other consumer goods more effective and practical. Also projected is the regulation of distribution system in such a way that the general public are able to procure or purchase essential commodities at reasonable rates".

Our Embassy in Kathmandu had asked for the official version of the statement of the Ministry of Commerce and Industry and sought clarification on the applicability of these regulations to Indian Nationals in the territory of Nepal.

It is my regret that due to difficulties in communications these could not be obtained in time for me to make a statement earlier.

With your permission, Sir, I now place on the Table of the House a copy of the official press release of His Majesty's Government of Nepal. [*Placed in Library. See* No. LT-5972/73.]

It has been stated that raw jute and jute cuttings will be exported only through the National Trading Ltd.

[Prof. D. P. Chattopadhyaya]

These would represent about 50 per cent of the total exports from Nepal. It has also been stated that barter trade with overseas countries is reserved as heretofore for the public sector. Wrile exact figures are not available it is believed that these would form a significant proportion of the balance of exports.

It has been pointed out by the Ministry of Commerce and Industry of Nepal that the prohibition on firms run by foreigners or in collaboration with the foreigners is not confined to jute goods but extends to the export and import of all goods.

His Majesty's Government of Nepal have explained to our Charged' Affaires in Kathmandu that the restrictions do not apply to imports from and exports to India and that Indian nationals or firms taking part in trade between India and Nepal are not affected. It has also been explained that if a firm is trading both with India and with third countries, its trade with India will not be affected by the new regulations.

It is the contention of His Majesty's Government of Nepal that the restriction on imports from and exports to third countries is not in contravention of Article 7 of the Treaty of Peace and Friendship. It is also their contention that while it is the objective to better utilize the technical know how and resources of foreigners in the field of industry instead of in trade, the new regulations would also curb deflection of third country goods to India through Nepal and thereby remove a source of irritation in relations between India and Nepal.

The new regulations are being examined by the Government of India in the light of the clarifications given by His Majesty's Government of Nepal. The Government of India will have further consultations with His Majesty's Government of Nepal. It is the view of the Government of India that while pursuing the common objective of healthy growth of trade and mutual cooperation between the two countries, the two Governments grant on a reciprocal basis to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of participation in trade and commerce.

श्री शशि भूषण : अध्यक्ष महोदय, नेपाल के साथ हमारे बड़े अच्छे मित्रता के सम्बन्ध हैं। इतने अच्छे मित्रता के सम्बन्ध हैं जो दुनिया के दूसरे देश भी उस को एक उदाहरण मान सकते हैं, और इसी मित्रता की स्पर्धा में नेपाल का पडौसी देश चीन भी उन से बहुत मित्रता दर्शाने का प्रयत्न कर रहा है: इस में कोई गलत बात भी नहीं होती, मित्रता तो सब देशों के साथ होनी चाहिए लेकिन चीन के साथ मित्रता के साथ साथ तिब्बत और भारत की सीमा का अधिकाधिक ध्यान रखना चाहिये हमारे और नेपाल के इतने अटूट सम्बन्ध हैं कि नेपाल सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जाता है तो हिन्दुस्तान के दिल पर ठेस लगती है, और जो उन्होंने यह विनियमन किया तो हमारी जो 1950 की पुरानी संधि थी उस के मुताबिक अगर वह सिर्फ भारत सरकार से थोड़ा सलाह मश्विरा कर लेते या हमारे दूतावास से सलाह मश्विरा कर लेते तो मुनासिब होता। और मुझे पता नहीं कि उन्हों ने नया विनियमन लागू करने पर कुछ इस ढंग का इशारा भारतीय दूतावास को दिया कि नहीं ? यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो भारत के व्यापारी वहां हैं उन में बहुत से ऐसे हैं जो 150 साल से व्यापार कर रहे हैं और आजादी के बाद 50 फर्में ऐसी हैं जो हिन्दुस्तान में भी और नैपाल में भी इन्कम टैक्स देती हैं, और हमारे दूतावास की सिफारिश के मुताबिक उन को वहां एक्सपोर्टर के तौर पर रजिस्टर किया गया है। कुछ फर्में, लगभग 25, 30, ऐसी हैं जो हिन्दुस्तानी व्यापारी और नेपाली व्यापारी दोनों मिल कर पार्टनरशिप में चलाते हैं। इन सब पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह मैं जानना चाहता हूं। लेकिन एक बात जरूर है कि जो नैपाल ट्रेडिंग संस्था है, जो

वहां की राष्ट्रीय संस्था है, जैसी कि हमारे यहां एस० टी० सी० है, तो क्या आप एस० टी० सी० के द्वारा उन के साथ अधिक से अधिक सम्बन्ध बना कर यहां जो क्षति हुई है हमारे व्यापारियों को उसे पूरा कराने का प्रयत्न करेंगे।

साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि नेपाल में जो लोग वहां मौजूद हैं उन के साथ भी हमारे दूतावास ने वहां के व्यापारियों की संस्थाओं से बातचीत की है, और नेपाल सरकार तथा व्यापारियों के बीच में बातचीत कराने के सिलसिले में उन्होंने कोई कदम उठाया है।

साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो भी विनियमन वहां लागू किये गये हैं, जो मुनासिब हैं, लेकिन ऐसे समय पर लागू किये गये हैं जब नैपाल के नरेश की यात्रा चीन को होने वाली है। तो इस से थोड़ा संदेह लोगों को यह है कि चीन कुछ नेपाल के अन्दर इस बात का प्रयत्न करता है कि भारत और नेपाल के सम्बन्ध अच्छे न हों। ऐसी हालत में, मैं भी इस पर कोई विश्वास नहीं करता और पिछली बार मंत्री जी ने राज्य सभा में इस का खंडन किया है, लेकिन इस से संदेह जरूर होता है कि नैपाल में कुछ विदेशी ताकतें भारत और नैपाल की अगाढ़ मित्रता को देख कर रश्क करती हैं और प्रयत्न करती हैं कि यह सम्बन्ध किसी तरह बिगड़ें। लेकिन हम हमेशा इस बात का प्रयत्न करते रहे हैं कि नेपाल से मित्रता हो। इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे व्यापारिक सम्बन्ध और आगे बढ़ें और नेपाल का ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो उस सम्बन्ध में आप का विभाग क्या कदम उठाने जा रहा है।

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Two or three questions have been raised by the hon. member. The first was whether our trade relations with Nepal were likely to be affected by the recent decisions of His Majesty's Government. It is too early to give a very definite answer to the question without looking into the details and further implications of the view taken by the Government of Nepal.

The other question was whether we envisaged any sort of extended trade relations between STC and National Trading Limited. This may be taken up when the next meeting of the Joint Review Committee takes place sometime late this month.

As to the possibility of China's influence underlying this decision of His Majesty's Government, I can only say there is no reason to believe it because this is a decision of HMG taken on their own, may be having their own understanding of the requirement of their national and industrial necessity. So I do not think there is any ground for speculating in that unwarranted direction.

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : अध्यक्ष महोदय, नेपाल के साथ हमारे बहुत पुराने सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक सम्बन्ध है और नेपाल तथा भारत को अलग नहीं किया जा सकता है। यद्यपि ये दो देश हैं, लेकिन हमारे पारस्परिक सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हैं। हमारे देशों की सरहद किसी नदी या पहाड़ के आधार पर नहीं बनी हुई है, बल्कि वहां स्थिति यह है कि यदि किसी का घर इधर है, तो वह काम उधर करता है और सरहद के दोनों ओर आना-जाना, खाना-पीना निर्विघन रूप से होता है। आज नेपाल में जिस तरह की सरकार है, उस को बनाने में हमारी सरकार और पुरानी जेनीरेशन के राजनैतिक कार्यकर्ताओं का भी कान्ट्रीब्यूशन था।

सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया है, वह बड़ा नपातुला है, सरकार ने इस में बड़ी समझदारी दिखाई है और मैं

(श्री विभूति मिश्र)

इस की भूरि- भूरि प्रशंसा करता हूं। लेकिन अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि नेपाल में हमारे शर्ज-द-फेयर की चार दिन तक परिश्रम करने के बाद वहां के कामर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर से मुलाकात हो पाई। इस से यह पता चलता है कि वहां पर कुछ खामी है और वहां पर हमारे खिलाफ कुछ कार्यवाही हो रही थी। नेपाल दो बड़े देशों के बीच में स्थित है और चारों तरफ के देश वहां पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। मंत्री महोदय ने श्री शशि भूषण के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि कुछ अन्य देश भारत और नेपाल के पारस्परिक सम्बन्धों को बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस के पीछे कोई बात अवश्य है। क्या करण है कि नेपाल के किंग के चाइना जाने से कुछ दिन पहले यह घोषणा की गई ? जब चाणक्य ने एक चींटी को एक दाना ले जाते हुए देखा, तो उस के दिमाग में आया कि यहां गल्ला जरूर है। इसी तरह इस मामले में भी कुछ सन्देह का कारण अवश्य है और इस दृष्टि से मंत्री महोदय का जबाब असंतोषजनक है।

जहां तक भारत और नेपाल के बीच व्यापार का सम्बन्ध है, मुझे ऐसा लगता है कि अन्य देशों का सामान नेपाल में जायेगा और दोनों देशों के बीच कोई नैचरुल बाउंडरी न होने के कारण स्मगल हो कर भारत में आयेगा, जैसे कुछ समय पहले स्टेनलेस स्टील का सामान नेपाल से हमारे देश में आता था और हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था को नुक्सान होता था। बाद में नेपाल के साथ हमारी जो ट्रीटी हुई, जिस के लिए मैं श्री एल० एन० मिश्र को धन्यावद देता हूं, उस से स्थिति में कुछ सुधार हुआ। लेकिन इस बयान से मालूम होता है कि हमारे व्यापार को जरूर नुक्सान पहुंचेगा, क्योंकि हमारे यहां के व्यापारी वहां रहते हैं और वहां के व्यापारी यहां रहते हैं।

मंत्री महोदय ने कहा है कि वह इस मामले में जांच करेंगे, और अगर आवश्यक हुआ, तो इस बारे में नेपाल सरकार से बातचीत की जायेगी और तब सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। यद्यपि हम लोग कामर्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की तरह विशेषज्ञ नहीं हैं लेकिन हम को लगता है कि इस से हमारे व्यापार को नुक्सान होगा।

मैं चाहता हू कि विदेश मंत्री, सरदार स्वर्ण सिंह, जो बड़े निपुण आदमी हैं और हमारे आज के चाणक्य हैं, इस बारे में नेपाल सरकार से बात करें और इस बात का पता लगायें कि इस घोषणा से हमारे व्यापार को क्षति होगी या नहीं और अगर होगी, तो किस हद तक। मैं इस बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां से जूट स्मगल हो कर नेपाल में जाता है। नेपाल सरकार ने जूट पर 5 परसेंट बोनस दिया है। इस तरह नेपाल का जूट सस्ता पड़ेगा और हमारा जूट महगा पड़ेगा।

नेपाल के साथ जो ट्रीटी हुई है,उस के अनुसार दोनों देशों में बना हुआ सामान एक दूसरे के यहां भेजा जा सकेगा और उस पर डयूटी नहीं लगाई जायेगी। लेकिन अब नेपाल दूसरे देशों के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर रहा है। इस बात की सम्भावना है कि थर्ड कन्ट्री का सामान नेपाल जायेगा और उस पर नेपाल की मुहर लगा कर यहां भेज दिया जायेगा। तब हम क्या करेंगे ? हमारी लाचारी यह है कि उस सामान पर नेपाल की मुहर होगी, भले ही वह किसी अन्य देश का सामान हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार से बातचीत करेगी; यदि हां, तो

कब तक । जो सामान अन्य देशों से नेपाल आयेगा, क्या उस की निगरानी के लिए भारत का कोई अधिकारी रहेगा ? ट्रीटी में यह तय किया गया है कि हम उस सामान को देख नहीं सकते हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस बारे में एग्जामिनेशन करने के बाद सरकार को कब तक यह पता लग पायेगा कि नेपाल सरकार की इस घोषणा का हमारे व्यापार पर क्या असर होने जा रहा है ।

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: The hon. Member who comes from a region which is very close to Nepal has very rightly pointed out—as he knows—the close cultural and historical relations between our two countries.

This proximity of these two friendly countries has its own problems, to some of which he has referred, namely, some unwholesome practice of trade indulged in by some unscrupulous elements and thereby creating some avoidable irritants in our relations. We are seized of the problems. The customs arrangements have been strengthened; the vigilance squad has also been strengthened. We also hold periodical meetings to look into the specific difficulties and remove them.

About the breakdown of communications, I can only say that it is a mechanical failure. Not that our people in the Khatmandu Embassy were not vigilant.

श्री विभूति मिश्र : 7 तारीख़ के सर्चलाइट में लिखा है कि नेपाल में हमारे शाज-द-फ़ेयर को नेपाल के सम्बद्ध मंत्री के साथ मुलाकात करने में चार दिन लगे ।

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Sir, actually, there was a breakdown of communications. So, we could not get fuller information and, as you will kindly appreciate, in such an important and sensitive matter, without having the necessary clarification, it would not be perhaps correct on our part to submit some information before this august House.

Our problems, which are not really problems—I might say they are issues—about trade and transit have been well taken care of; that is in the treaty of trade and transit negotiated and concluded by Mishraji sitting here.

There are some very good provisions in that treaty which are being observed to facilitate the trade of Nepal with India and other countries. So, so far as that part is concerned, we think that the provisions that are there are good enough, both substantive and procedural, to look after the problems which might crop up periodically between these two countries.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, भारत और नेपाल के बीच में दोस्ताना रिश्ता रहे और बढ़े इस का मैं हमेशा समर्थक रहा हूं और मैं यह चाहता हूं कि नेपाल के सच्चे औद्योगीकरण में भारत पूरी मदद दे । लेकिन कुछ भारतीय तत्व भारत और नेपाल के बीच में जो सन्धियां हुई हैं उन में जो कमियां थीं उनका फायदा उठा कर जो दोनों देशों को लूटने का काम करते थे उस का मैं ने हमेशा विरोध किया है ।

जहां तक अपने वैदेशिक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का सवाल है नेपाल की सार्वभौमिकता को हम लोग मानते हैं । इसलिए यदि वे अपने वैदेशिक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं जो तीसरे देशों के साथ होता है तो उस पर एतराज करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होना चाहिए, यह मेरी राय है । अगर उस में कुछ भारतीय

[श्री मधु लिमये :]

व्यापारियों का नुकसान भी होता है तो उस में हम को दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि नेपाल की सरकार ने कहा है कि जहां उन्होंने तीसरे देशों के साथ जो व्यापार होता है उसका कुछ सरकारीकरण करने का इस में प्रयास किया है वहां नेपाल और भारत के बीच में जो आयात-निर्यात व्यापार होता है उस पर इस का असर नहीं पड़ने वाला है, यह भी कहा है। इसी बात को हमें देखना है। बाकी जो तीसरे देशों के साथ उन का व्यापार है उस में पड़ने की जरूरत नहीं है। नेपाल की सरकार ने यह कहा है, एक वाक्य मैं आप के सामने रखना चाहता हूं :

"It is also their (Nepalese Government's) contention that while it is the objective to better utilise the technical know-how and resources of foreigners in the field of industry instead of in trade, the new regulations would also curb deflection of third country goods to India through Nepal and thereby remove a source of irritation in relations between India an Nepal."

पहले बड़े पैमाने पर व्यापार की दिशा में फेर-बदल होता था, डीफ्लेक्शन आफ ट्रेड होता था। एक तो भारत में जो जूट का सामान बनता था कस्टम के लोग दूसरों के साथ मिल कर भारतीय माल पर नेपाल का सिक्का लगा देते थे और बिना एक्सपोर्ट डयूटी दिए हमारे बन्दरगाहों से भारतीय माल चला जाता था। बम्बई में भी कई आफिसर आकर सिक्का लगाते थे और कलकत्ता में तो यह होता ही था। इस की जानकारी जब दिनेश सिंह जी व्यापार मंत्री थे उसी जमाने से मैं सरकार को देता आया हूं। दूसरा ट्रेड डी-फ्लेक्शन यह होता था कि नेपाल में तीसरे देशों का जो सामान आयातित किया जाता था स्टेनलेस स्टील, शराब और सिंथेटिक धागा और कपड़ा जो वास्तव में जापान में बनता है उस के बारे में भी उस समय मैं ने श्री बलि राम भगत को बताया था कि वह भारत में आ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो नया करार किया गया है उस का प्रोटोकोल आप देख लीजिएगा, उस में आर्टिकिल 4 के संबंध में यह खुलासा किया है :

"The Government of India will provide access to Indian market free of basic customs duty and quantitative restriction generally for all manufactured goods which contained not less than 90 per cent of Nepalese materials or Nepalese and Indian materials."

तो इस में एक वाक्य है नई सन्धि में कि जो नेपाल के कच्चे माल से बना हुआ सामान है उस पर डयूटी नहीं लगेगी। लेकिन जो माल तीसरे देशों से आता है और "मेड इन नेपाल" का सिक्का जिस पर लगाता है वह अब नहीं चलेगा।

इस में आगे यह भी कहा गया था :

"In the case of other manufactured articles in which the value of Nepalese material and labour added in Nepal is at least 50 per cent of the ex-factory price, the Government of Nepal will decide in each case the nature and extent of the access, including tariff preferences having regard to all relevant factors."

अब मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि पुराने जिन सामानों को ले कर एक विवाद का विषय खड़ा हो गया था, स्टेनलेस स्टील आता था, थीड़ा मोड़ दिया जाता था और फिनिश्ड गुडस कर के आता था सिंथेटिक कपड़ा और धागा आते थे, शराब आती थी, इस के बारे में बहुत बड़ा प्रीमियम उन लोगों को मिलता था।

अब क्योंकि खुद नेपाल की सरकार ने ट्रेड-डीक्लेक्शन को रोकने की बात की है तो क्या मंत्री महोदय इस बात का खुलासा करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या क्या सामान आता है, जो पहिले आता था उस में से कितना रोका गया । इस वक्त रुपये में बताएं कितना आ रहा है क्योंकि 1971 के बाद दो साल तो हो गए हैं । अब आप एक मूल्यांकन रिव्यू सदन के सामने रख सकते हैं ।

जहां तक नेपाल के औद्योगीकरण का सवाल है मेरी अपनी राय है कि हम लोगों को इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए । आप के यहां बिजली की बहुत कमी है । यह जो कोयले का मामला है, रेल का मामला है और तेल का मामला है, जिस के "महान" मंत्री यहां बैठे हुए हैं, वह तो आप जानते ही हैं तो मेरा कहना यह है कि नेपाल के पास जल-शक्ति विपुल है, आप को बिजली की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि नेपाल का औद्योगीकरण तेजी से हो तो क्या सरकार नये सिरे से नेपाल के साथ इस विषय पर विचार करेगी ? तो जल-शक्ति का विद्युत शक्ति में परिवतन करने के लिए नई योजनाएं बनाई जांय, कुछ हिस्सा नेपाल अपने लिए रखें, बाकी भारत को बेचें ताकि नेपाल को पैसा भी मिले और बिजली की जो बहुत बड़ी कमी हमारे यहां है, खास कर के उत्तरी भारत में, उस की आंशिक पूर्ति के लिए रास्ता खुल जाये ? मंत्री महोदय मेरे इन दो तीन मुद्दों को जिन को मैं ने संक्षेप में रखा है स्पष्ट करने का कष्ट करें ।

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: We fully share the hon. member's feeling that His Majesty's Government has every right to regulate and if necessary nationalise its trade and industry in the interest of their country. There is no question about it because any sovereign country has its own right to regulate and nationalise its trade when it thinks it necessary. It is also true that in the clarification obtained and also in the previous documents between these two counies, it has been stipulated that both the countries will take every possible step to see that third country's goods do not find entry into the other country causing inconvenience and loss to the exchequer of the country concerned. I have already referred to that unwholesome practice. The customs arrangements have been strengthened and the vigilance squads have also been strengthened. The hon. member asked whether the quantum of deflection could be precisely indicated. It is very difficult to quantify the deflection because it is not known.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इन को थोड़ी गलतफहमी है । मैंने उस को क्वांटिफाई करने के लिए नहीं कहा था । मैंने यह कहा था कि नेपाल से स्टेनलेस स्टील सिंथेटिक फैब्रिक्स और शराब तो पहले आती थी जिस के आंकड़े सरकार के पास हैं । उस पर आप ने रोक लगाई है और कहा है कि नेपाल का माल 90 परसेंट तक होना चाहिए तो क्या इस तरह के सामान भी इन दिनों में आ रहे हैं ?

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: If and when in the past this sort of problems about stainless steel, synthetic goods etc. arose, we looked into those problems. As I said, we are going to meet this very month and I think some of the questions raised by Limayeji will be taken up at that time. About the Indo-Nepal power project, it is a very potential area where our collaboration has strengthened. But since it pertains to another ministry I cannot go into details. But in principle I agree with it.

श्री मधु लिमये : विदेश मंत्री यहां पर बैठे हैं, वे भी इस के सम्बन्ध में कुछ कहें ।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): I would like to add that some preliminary discussions have taken place between our Ministry of Irrigation and Power and the Government of Nepal to decide upon certain projects where hydro-electric power might be generated. As the House knows, in this respect, there has been very good cooperation between India and Nepal in the matter of canals and anti-flood measures and the stage has been reached when we can cooperate to establish a hydro-electric project in Nepal. As suggested by Mr. Limaye, they can retain the electricity for their own requirements and we can assure them that whatever surplus is left, we will be prepared to purchase it at a reasonable negotiated price

•SHRI NAWAL KISHORE SINHA (Muzaffarpur): In view of para 9 of the statement and the fact that His Majesty's Government of Nepal have made it clear that they have no intention to water down the provisions of article 7 of the Indo-Nepalese Treaty, I have no questions to put.

12.30 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

STATEMENT RE. EXTENT OF REDUCTION OF CRUDE OIL IMPORTS BY FOREIGN OIL COMPANIES AND REPORT OF TARIFF COMMISSION ON PRICE STRUCTURE OF BETA OXY NAPHTHOIC ACID.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): I beg to lay on the Table:—

(i) A statement regarding the extent of reduction in crude oil imports by the foreign oil companies, particularly Caltex.

(ii) A copy of the Report (1966) of the Tariff Commission on the price structure of Beta Oxy Naphthoic Acid (Hindi version) under sub-section (2) of section 16 of the Tariff Commission Act, 1951.

[*Placed in Library. See* No. LT-5962/73].

COMPANIES (PUBLIC TRUSTEES) RULES, 1973.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BEDABRATA BARUA): I beg to lay on the Table—

A copy of the Companies (Public Trustee) Rules, 1973 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 983 in Gazette of India dated the 15th September, 1973, under sub-section (3) of section 642 of the Companies Act, 1956 [*Placed in Library. See* No. LT-5963/73].

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

INTERIM REPORT

SHRI B. S. MURTHY (Amalapuram): I beg to present the Interim Report of the Railway Convention Committee, 1973.

12.31 hrs.

STATEMENT RE. CORRECTION OF INFORMATION GIVEN DURING CALLING ATTENTION ON 6-12-73

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): On behalf of Shri D. K. Borooah, I wish to make the following statement:

"I regret to say that in the debate on the 6th December, 1973 on the